

but I don't think in any other Constitution, you will ever be interested.

SHRI PILOO MODY. Probably not. In any case Mr. Mujibur Rahman's Constitution is not acceptable to us.

MR. SPEAKER. Should we have some extra time? May I request all of you to please listen? Can the Prime Minister reply today or tomorrow? Because, just at the end, I have received many requests by hon Members. As you know, I can extend the time if you like by half an hour or one hour because the Business Advisory Committee has given me latitude for allotment upto one hour.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) You may extend it by one hour It will not be over today. We should get that one hour.

MR. SPEAKER. So, the Prime Minister will be replying tomorrow; if we extend time by one hour as you decided, I will exercise it in favour of Members.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Members should get that one hour; Mr Somnath Chatterji has to speak.

SHRI PILOO MODY: When it is extended by one hour, you should get 1½ minutes

12.04 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS' ADDRESS—Contd.

श्री प्रताप सिंह नेगी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण पहले हिन्दी में और उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ा। मैं समझता हूँ कि यह हमारे

लिए बड़े गौरव की बात है क्योंकि हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया है। हम हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहते हैं। जब ऐसी बात है तो यहाँ पर हिन्दी में बोलना हम अपनी बहुज्जती समझे तो यह बात ममझ में नहीं आती है। इसलिए यह फरक की गान है कि राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण हिन्दी में पहले पढ़ा और बाद में अंग्रेजी में।

मुझे यह कहने हुए बिल्कुल भी शिंशक नहीं है कि राष्ट्रपति ने देश में जो बलु स्थिति है उसका एक मही चित्रण हमारे सामने किया है। किस तरह से इस स्थिति से सरकार निपटना चाहती है, इसका विवरण भी उन्होंने अपने अभिभाषण में किया है। हम आशा करने हैं कि देश आगे तरक्की करना हुआ बढ़ना जायेगा। हमारे विरोधी भाई देश में सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, बरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महगाई है। अपने भाषणों में इन सब का राग भलापते नहीं थकते हैं। मैं मानता हूँ कि देश में महगाई है, भ्रष्टाचार है, तथा दूसरी बातें हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये बाने हैं क्या। जब आप लोग मिलो, कारखानों आदि में हड़ताल कराते हैं तो इसका स्वाभाविक तौर पर यही नतीजा निकलेगा कि पैदावार बन्द हो जायेगी और महगाई अपने आप बढ़ेगी। मैं तो कहना हूँ कि इस महगाई के लिए भी मेरे बही भाई जिम्मेदार हैं जोकि इस महगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनका केवल एक ही मकसद होता है कि किसी प्रकार से सरकार को बदनाम किया जाँ और अपना उल्लू मीघा किया जाये ताकि अन्त में देश की बागडोर उनके हाथ में आ सके। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि भारत की जनता आज जागरूक हो चुकी है। वह जान चुकी है कि कौन उसका हितैषी है और कौन उसके हितों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये चाहे जितने मगरमच्छ के घासू बहाते रहें जनता के ऊपर इसका कोई असर

[श. प्रताप सिंह नेगे]

नहीं पड़ सकता है। आज तक जो पाच धाम चुनाव हुए हैं वे इस बात के साक्षी हैं कि जनता इनके साथ नहीं है, हमारे साथ है। यह मैं उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ।

मुझे इस समय एक बात याद आती है। एक बार इंग्लैंड में श्री बर्नार्ड शाह धूमने जा रहे थे। उनके साथ उस समय एक मोटे व्यापारी भी थे। रास्ते में चलते हुए, उस व्यापारी ने बर्नार्ड शाह से कहा कि अगर कोई आपको देख ले तो यही कहेगा कि इंग्लैंड में भुजमरी है। इस पर उन्होंने तपाक में जवाब दिया कि बिल्कुल ठीक बात है लेकिन आपको देख कर उसको भुजमरी का कारण भी नजर आ जायेगा। वही हानन आज हमारा यहा है। हम मानते हैं कि हमारे यहा बेकारी है, बराजगारी है, भुजमरी है लेकिन इसका कारण भी जनता को मालूम हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे विरोधी दल वालों का जो रबैया रहा है वे समझे कि वह ठीक नहीं रहा है, वे अब भी सम्भल जायेंगे और कोशिश करेंगे, सरकार के साथ मिल कर काम करेंगे, सरकार की जो गलतियाँ हैं उनको सरकार को बतायेंगे और सही रास्ते पर सरकार को लाने की कृपा करेंगे ताकि देश की नाव अच्छी तरह से पार हो सके।

आज देश में ऐसे अनासर भी सिर उठा रहे हैं जोकि सेना को अनुशासन भंग करने के लिए भड़का रहे हैं, और देश के सविधान को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार ने काफी समय तक सब से काम ले लिया है। आप ने काफी इस पर सोचा है, काफी उनको मौका दिया है। अब भी मौका आया है सेना ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई है ऐसे वक्त पर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वह दिखा चुकी है। ऐसी बहादुरी उसने बिनाई

है कि कुछ ही दिनों के अन्दर अन्दर 93,000 दुश्मन के सैनिकों से हथियार डलवा दिये हैं और देश के माथे को ऊंचा किया है। ऐसी सेना को अनुशासन भंग का उपदेश देना, अनुशासन भंग कराने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, मैं समझता हूँ कि देश के माथे गद्गारी करना है और इससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनके बारे में पूरे उपाय आपको अभी से कर लेने चाहिये।

इसके अलावा एक और बात भी है। हमारी प्रधान मंत्री जी ने बड़ी मूलबूझ के साथ, बड़ी योग्यता के साथ राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए श्रेष्ठ प्रबुद्धता माहब के साथ एक समझौता किया है। उस समझौते के फलस्वरूप श्रेष्ठ माहब ने जम्मू काश्मीर की बागडोर सम्भाल ली है, वहा मुख्य मंत्री की गद्दी पर बैठ गये हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मार्शल भूट्टो साहब आज बड़े जोरो से बावैना मचा रहे हैं और अपने देश में हड़ताल तक करने का आह्वान कर रहे हैं। यद्यपि यह हमारा आंतरिक मामला था और उन्हें इसमें बोलना भी नहीं चाहिए था लेकिन वह बोले जिसका हमें दुख है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख हमें तब होता है जब हम देखते हैं कि हमारी मसद् के अन्दर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जोकि इस समझौते के खिलाफ भूट्टो साहब की आवाज से आवाज मिला कर इसका विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, और यह सदन भी जानता है, कि भूट्टो अपने आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अमरीका की आवाज उनकी जुबान से निकलती है, वह अमरीका के इशारे पर नाचते हैं और उसके इशारे पर बोलते हैं। क्या मैं मान लूँ कि हमारे जो भाई वहाँ पर इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, वे भी अमरीका के एजेंट हैं? अगर मैं यह मान लूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई चुनाव का दावा नहीं कर रहा हूँ।

मुझे अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में भी कुछ निवेदन करना है। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ है। हमारे यहाँ एसेम्बली का एक क्षेत्र लगभग 5 000 वर्ग किलोमीटर का पड़ना है। हमारे घाट पहाड़ी जिलों की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का 4 परसेंट है, लेकिन हमारा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 17 परसेंट है। हमारा क्षेत्र पहाड़ी है, ऊबड़-खाबड़ है और वहाँ धानधान के माधनों का बिल्कुल अभाव है।

श्री श्री मुझे मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना के लिए 1975-76 में लगभग 106 करोड़ रुपया रखा गया है। लेकिन आप को यह ज्ञान कर ताज्जुब होगा कि इन 9 पहाड़ी जिलों के लिए केवल 25 करोड़ रुपया रखा गया है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब में रुपया बांटा जाता, तो हम 60 करोड़ रुपयों के हफ्तागत होत। लेकिन ऐसा नहीं किया गया? क्या नहीं किया गया? — हमें लिए कि हमारी आबादी कम है। लगभग 430 सदस्यों की एम्ब्लसी में हमारे यहाँ के केवल 19 प्रतिनिधि हैं और 19 प्रतिनिधियों की आवाज वहाँ नक्कारखाने में नती की आवाज के समान है।

जहाँ तक हमारे लिए यात्रा करना बनाने का सम्बन्ध है, अगर हमारे यहाँ के पहाड़ों की चोटियों पर और घाटियों में जा कर वहाँ की आबो-हवा, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के हिमपात को देख कर योजना बनाई जाये, तब तो हमारा कल्याण ही भकता है। लेकिन अगर लखनऊ में बिजली के पखें के नीचे बैठ कर हमारे लिए योजना बनती है, तो हम कभी कल्प नहीं सकते हैं, हमारा कभी विकास नहीं हो सकता है। मैं तो हम नतीजें पर पहुँचा हूँ कि अगर सरकार हमारे इन 8 पहाड़ी जिलों को अलग प्रान्त का दर्जा दे दे, तो हमारा कल्याण हो सकता है, हम को भीका मिल सकता है कि हथ अपने क्षेत्र के उत्थान और विकास के लिए कुछ कर सकें।

हमारे यहाँ अपार जल-सम्पत्ति है, खनिज पदार्थों का भंडार भरा हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ अपार वन-सम्पदा है। उसका दोहन हो रहा है, लेकिन हमें उससे लाभ नहीं मिलता है। हमारा कारण यह है कि हम अपने क्षेत्र को केवल रक्षक हैं, मगर हम उसके विनाश के लिए कुछ नहीं कर सकते।

श्री श्री पिछले दो वर्ष पूर्व एक पर्वतीय विकास परिषद बनाया गया, लेकिन वह परिषद बिल्कुल पगु है। उसके हाथ में कोई ताकत नहीं है। वह कोई निर्णय नहीं ले सकता है और न ही कोई योजना बना कर उसको कार्य रूप में परिणत कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा और अधिकार नहीं है। हमारे विभागों में बनाए कर्के उसमें योजना बनानी है, और उसके बाद भी उसको कार्यान्वित नहीं कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की वजह यह है कि अगर किसी योजना को अमलमें लाना पड़ता है तो फलक का टोका पर्वतीय विकास परिषद् पर पड़ेगा। मैं ममअना हूँ कि यह विकास परिषद् हमारे विकास के लिए नहीं है बल्कि वह हमारे लिए एक प्रकार में अभिशाप है।

आज हमारे लोगों की क्या दशा है, आप यह दिल्ली की शम्शी-ओपडियों में जा कर देखिये। हमारे पहाड़ी या तो वर्तन भाजने वाले मिलेंगे या दूसरे किस्म के घरेलू नौकर मिलेंगे। वे लोग शम्शी-ओपडियों में किस बुरी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप यह देखेंगे, तो आप के दिल दहल जायेंगे, आप पसीजा जायेंगे, और आप हमारी दरखवास्त को मजूर करने के लिए जरूर तैयार हो जायेंगे।

मैं और कुछ न कहते हुए राष्ट्रपति महोदय को उनके सुन्दर अभिभाषण पर अनेक धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के इन 8 पहाड़ी जिलों का अलग क्वाल रखेगी। अगर वह

[श्री प्रतप सिंह नेग]

उनको बलग प्रान्त का दर्जा देगी अगर अभी नहीं दे सकती, तो कम से कम उनको एक केन्द्र-शासित प्रान्त बना दिया जाये, यह मेरी लक्ष्य शब्दों में और बलपूर्वक दरखास्त है। इस समय हमारे विरोधी भाई वर्तमान स्थिति से नाजायज लाभ उठा रहे हैं। हमारे नौजवान सीमात पर पहरा देते हैं, लेकिन उनको हर बक्त फिक्र रहती है कि घर में हमारी बीबी बचेली रहती है, उसको पानी के लिए दो मील नीचे जाना पड़ता है, जब तक वह पानी का घड़ा लेकर आयेगी, तब तक बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनकी सफाई धुलाई कैसे की जायेगी। बहू शिक्षा का भी यही हाल है।

मैं फिर एक बार सरकार में, श्रीर खास तौर में अपनी प्रधान मंत्री जी से, जिनका सिद्धान्त ही यह है कि देश में समाजवाद लाया जाये और गरीबी को हटाया जाये, दरखास्त करना हू कि वे इस पहाड़ी क्षेत्र की तरफ ध्यान देकर मेरी मांग स्वीकार करने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद-प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

SHRI C. H. MOHAMED KOYA (Manjeri): Mr Speaker, Sir, when the President addressed both the Houses of Parliament, my party could not attend Parliament because of the situation in the Jama Masjid area. Sir, there was also no mention of this in the President's Address. Sir, this matter has been discussed in the House several times. I do not want to add anything except to request the Government to order a judicial enquiry because so many allegations have been made by Members including responsible members like Shrimati Subhadra Joshi. Sir, the truth can be found out only if a judicial probe is ordered. Sir, if we do not do that, the police will

not act in a tactful manner in situations like this. Sir, if the Police had acted with some tact, innocent people would not have been massacred in old Delhi. Therefore, Sir, I would request the Home Minister to order a judicial probe into this matter when the situation becomes normal.

Sir, the President has mentioned about the Government's action in regard to economic offences and I am very happy that it had its desired effect. But, Sir, Government will have to be very cautious in this matter because they always depend on the reports of the officers who are prejudiced and who sometimes act in a very communal way. Sir, there is a feeling in Kerala that MISA was used with a communal bias. In the past, so many innocent people have been detained under the Defence of India Rules and other Acts because of the reports of the officers. These people do not have the right to appear in a court of law and defend themselves. Therefore, a review must be effected very seriously and innocent people should not suffer because of the baseless reports motivated by the communalism of the officers dealing with this.

I am here reminded of a small incident in Kerala where a man was arrested but was released on parole to attend the marriage of his daughter. The next day the son-in-law was arrested under MISA for an offence said to have been committed in 1972. This is the cruel way in which officers behave. If they wanted to arrest him, they could have done so the previous year before that. They did not do that. They waited till the marriage was celebrated. The officers knew that the marriage was going to be celebrated. Just think of the worry of the bride who was separated from her husband the next day when they should have been together on a honeymoon. The officers could have waited for a few more days when they and waited for three years.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): There is not a single member present in the Treasury Benches,

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI (Shajapur): I wanted to point out the same thing.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: It is being recorded and will be brought to their notice.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Under the rules, a Parliamentary Secretary is also a Minister.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: As I was saying, this is the cruel way in which the police officers function.

About smuggling, this has been going on for the last so many years Government is responsible for not tackling this.

MR SPEAKER: May I ask him to keep waiting for the Minister?

Let us see how much time they take to come here.—

Is there any Minister here?

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL) rose—

MR. SPEAKER: Someone is there.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: I hope my appeal will be heard by the solitary member in the Treasury Benches who is kind enough to be there when discussion on the policies of the Government is on. This is the irresponsibility of Government. They do not pay any heed to what we say about the policies of Government. Anyhow, I hope this will be recorded and sent to the Ministers and they will take Parliament seriously.

Another matter to which I wish to draw the attention of Government is the partiality shown in regard to the treatment of freedom fighters

who took part in what is known as the Malabar rebellion or the Moplah rebellion. The Kerala Government have considered them to be patriots deserving assistance and pension, but the Central Government in their wisdom consider that they are not patriots. Leaders like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru have testified to the fact that they were freedom fighters. Of course, it was true that towards the end of the rebellion some incidents had taken place, but all the same, they are freedom fighters. I have studied this. There are books written on the subject by Congress leaders in Kerala like Shri K. P. Keshava Menon and Shri Madhavan Nair who say that the rebellion was part of our national freedom struggle. But the Central Government here does not think so and refuses to give them pension. This partiality should be ended and Government should see that they are also given their pension.

It was really a horrible incident when the British Government put all the freedom fighters in a wagon and closed it. When the train reached Podanur, many people were found dead. There were Hindus also. These people are not eligible for pension. But those who ran away when the police came and were given an imprisonment of six months or more are given pension. This was brought to the notice of the Kerala Government and they have declared that these freedom fighters are eligible for pension. Unfortunately, the Central Government think otherwise. This communal partiality should end.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): The Communist Government in Kerala is also partial?

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: It is not communist. The hon. member should educate himself. He should know that the Congress is a party there.

I want to say something about the representation of the Muslim com-

[Shri C. H. Mohamed Koya]

ministry in services. Government should at least hold an enquiry and see what percentage of the Muslim community is in the services. They should take adequate measures to see that minorities get their representation in the Government services. Kerala is a neglected and backward State. By exporting tea, coffee, cardamom, ginger, timber and other things it helps the country as a whole to earn foreign exchange but it is neglected and it is suffering because we have not got enough food. Government of India must see that Kerala is given sufficient aid to maintain 12 oz. of ration because it produces things for export to earn foreign exchange for the Central exchequer.

I want to refer to the proposal for an aerodrome in Calicut. Malabar part of Kerala was a very big business centre but unfortunately that area has not been connected with the outside world. For the last 25 years there was this demand but the Government of India paid no heed. At last the Kerala Government even acquired the land. Approach roads had been constructed. But no action has been taken by the Government of India. Calicut is still not connected with the outside world. I hope the Government would take early steps in this direction.

The President refers to the shortage of electricity and power in the country. But unfortunately the hydro-electric schemes of Kerala are delayed for lack of funds. It is time that the Central Government assured the Kerala Government help to complete their hydro electric schemes because in that case it will make Kerala self-sufficient and Kerala can even supply electricity to neighbouring states of Tamilnadu and Mysore. A little help from the Central Government would solve the problem of electricity not only in Kerala but also in Tamilnadu and Karnataka as well. The Government of India is not paying any heed to the request of the Government of Kerala for help in this direction.

I am raising only small points. I do not want to refer to the economic situation in the country or the policy of the Government because the time at my disposal is short. Sitting on the vulcane of economic crisis the President addressed the two Houses of Parliament and there is no effective remedy to the illness. Prices are even going up. The poor man finds it difficult to make both ends meet. Government is increasing the D.A. of Government officers. So far, so good. But what about poor people, middle-class people, who struggle hard. They have not done anything in the matter. There is no effective policy so far as the ills of the country are concerned. What was the price of essential articles last year and what is the price now? I am not asking for any raise in the daily allowance of Members of Parliament. You think of the poor man. For arresting the rise in prices, no effective steps are taken.

SHRI N. K. P. SALVE: They have established for some months now.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: It may be all right for you but for the poor man it is very difficult. The price of a common man's daily necessities it still going up. The price of foodgrains had gone up and foodgrains are the most essential thing for the poor man. The Railway Minister in his wisdom has increased the freight on foodgrains. This is the contribution you are making to stabilise the prices. If essential articles like food, clothes and other things are not made available to the poor at reasonable prices, the economic problem of the country will not be solved. People will ask for more wages, there will be agitation for more wages, you will give them more wages and prices will again go up. People will have no fixed income. People who are at the starvation level find it very difficult. If they do not have adequate salaries to depend upon, how will they live? These things are not thought of at all, the position of the poor man is not thought of at all. Nothing

tangible, nothing effective, nothing creative has been done to arrest the rise in prices and we are still complacent saying that international prices have been rising. That is not the solution. What is the income of the average man in the other countries and what is the income of the average man in India? You simply take refuge under the statement that the international situation is bad and therefore our situation is also bad and therefore we have no solution. This is not the way to tackle this matter. I hope, therefore, Government will take up this matter very seriously and give priority to essential articles. It is alright that we have got an international name by nuclear explosion and all that but the poor man finds no solace in that. He has to get his food.

श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी (झमोरपुर) :
अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अधि-
भाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन का भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट के जितने मੈम्बर हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, वे देश की सद्भावना के साथ ही कोई बात यहां पर कहते हैं।

राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि आज देश में ऐसे बहुत से पिछड़े इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं जहां जमीन तो है लेकिन उस की उन्नति नहीं हुई है, क्योंकि उन को सुविधायें नहीं मिली—ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जायगा। उन्होंने यह भी कहा है कि आज 82 प्रतिशत वर्ग ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, जिन में किसान हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्याक हैं, इन लोगों को सही तरीके से उन्नति का लाभ नहीं मिला। इन के लिए न कहीं संगठन में जगह है और न सरकार में जगह है। इन लोगों की ओर अब विशेष ध्यान दिया जायगा।

हमारे यहां शिक्षा के लिए हमेशा कहा जाता है कि उम में आमूल परिवर्तन होगा, लेकिन वह परिवर्तन होता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन करना मंत्री के हाथ में नहीं है, परिवर्तन करना नौकरों के हाथ में है। आज नौकर हुकूमन में हैं। आज हर पार्टी कहती है कि देश से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए—लेकिन मिटे कैसे, क्योंकि सभी भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार कोई एक आदमी नहीं करना है या कोई एक पार्टी नहीं करती है, भ्रष्टाचार तो सब जगह है और सब से बड़ा भ्रष्टाचार तो यह है कि आज सब जगह कुनवापरस्ती और गुट परस्ती होती है। मान लीजिए—कोई अधिकारी इंजीनियर है, वह भ्रष्टवाल है, तो उस के विभाग में सारे भ्रष्टवाल भर जायेंगे। यदि कोई ब्राह्मण है, या कहीं मिनिस्ट्री में कोई ब्राह्मण है, तो उसका लडका भी मिनिस्टर होगा, खुद भी मिनिस्टर होगा उस की बहु भी मिनिस्टर होगी—इस तरह से कैसे चलेगा। आज हर तरफ से प्रजातन्त्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन प्रजातन्त्र है कहां ? जिस प्रजा का बहुमत है, जिन गरीबों का बहुमत है, उन के हाथ में कुछ भी नहीं है। आज जितने प्रैस हैं—वे किन के हाथ में हैं, सब पूजीपतियों के हाथ में हैं। आज राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है, लेकिन राष्ट्रीयकरण से खबराते हैं। क्यों खबराते हैं। राष्ट्रीयकरण अवश्य करना चाहिए, लेकिन अधूरा राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। हमारे यहां गेहूं का राष्ट्रीयकरण हुआ—लेकिन अधूरा हुआ किसी की नाक काट दी, किसी का कान काट दिया। सिर नहीं काटा। दुश्मन बना कर छोड़ दिया। इस लिए अगर राष्ट्रीयकरण करना है तो पूरा राष्ट्रीयकरण किया जाय और पूरी तरह से पूजीवाद को खत्म किया जाय, तब देश का कल्याण हो सकता है, लेकिन कौन करे ?

हमारे यहां अधिकारी लोग हैं, करोड़-पति हैं। हमारी पार्टी में भी कई आदमी ऐसे

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी]

हैं जो चाहते हैं कि लेक्चर देने से जनता सन्तुष्ट रहे और हम गरीबों का शोषण करते रहें। यह चीज अब बरदास्त नहीं की जा सकती। यहां पिछड़े वर्ग के कितने आदमी हैं—सब एक ही वर्ग के आदमी भरे हुए हैं। पार्टियों की भी यही हालत है। जनसंघ का नेता कौन है, संगठन कांग्रेस का नेता कौन है, कम्युनिस्टों का नेता कौन है—मुखर्जी साहब, सब ब्राह्मण हैं। ये सब लोग गरीबों की बातें करते हैं—लेकिन ऐसी हालत में गरीब आप की मदद कैसे करेगा ?

हमारे यहां बुलन्दशहर में एक इंजीनियर हैं—बंसल साहब। हमारे यहां के किसान उन के पास गए और कहा कि तुम जनता के नौकर हो। ईमानदारी से काम करो। उस ने कहा कि हम सरकार के नौकर हैं, तुम्हारे या जनता के नौकर नहीं हैं निकालो इन को। दूसरे दिन विवाद बढ़ गया, जो भी हुआ हो, किसी ने गाली दी हो या न दी हो, मारपीट भी हो सकती है। उस के बाद जो ब्लाक प्रमुख थे, उन के साथ झगड़ा हुआ, बाद में उन को और अख्यक्ष जिला परिषद को मिनिस्ट्री में बुलाया गया और कहा गया कि माफी मांग लीजिए। अब देखिए—अधिकारी बर्झमानी करे, बदमाशी करें और हड़ताल भ्रष्टाचार करे और हमारे लोग शिकायत सुनाने भायें तो उनको गाली दे और उस के बाद नतीजा यह हुआ कि वहां बिजलीवालों ने स्वयं हड़ताल कर दा, 5-6 दिन हड़ताल चली। उस के बाद यह मांग की गई कि जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं—स्वामी नेमपाल ज — वे इस्तीफा दें। इस का मतलब है कि कल अधिकारी लोग हड़ताल कर देंगे और कहेंगे कि बहुगुणा जी इस्तीफा दें। इसी तरह से केन्द्र के अधिकारी कहेंगे कि इन्दिरा जी इस्तीफा दें—इस तरह से कैसे चलेगा, नेमपाल जी ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं चुना हुआ आदमी हूँ माफी

नहीं मांगूंगा—जो भी बटना हुई है उसकी एन्कवायरी हो। अब नेमपालजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकारियों की इस कार्यवाही के खिलाफ हमारे यहां, 20-25 हजार आदिमियों का प्रदर्शन होने जा रहा है और मेरी अध्यक्षता में होने जा रहा है, क्योंकि मैं सब से ज्यादा भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ।

इस तरह मे भाग देखेंगे कि हर तरफ अधिकारी वर्ग का ही राज्य चल रहा है। अगर हम किसी मंत्री को कोई शिकायत लिख कर भेजते हैं तो मंत्री जी की तरफ से लिख कर आ जाता है कि आपकी शिकायत निराधार है। क्यों निराधार है, क्या मंत्री वहां जांच करने गये थे ? जो अधिकारी ने लिख कर भेज दिया, वही मंत्री लोग जवाब दे देते हैं। मैंने चव्हाण साहब के जमाने में भी लिख कर भेजा था, इनका जवाब भी आ गया कि आपकी शिकायत निराधार है। मैं एक सन्यासी हू, हर आदमी मुझे सच्ची बात कहता है, लेकिन वह बात निराधार इस लिये हो गई कि हमारे मंत्री वहां एन्कवायरी के लिये नहीं गये थे, नौकर एन्कवायरी के लिये गये थे जो लूट में हिस्सेदार होते हैं—तो इस तरह से यह नौकरो की हुकूमत है। अगर हमारे संविधान में इन नौकरो की हुकूमत खत्म नहीं की जायगी, तो हम संविधान का रखना बेकार है। अगर उससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उसको भाग लगा दी जाय। विधान खुदा ने नहीं बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है, मनुष्य ने मनुष्य के लिये बनाया है, उसके द्वारा सारे प्राणियों को सुख मिलना चाहिए। कुछ चीजें भगवान बनाता है—जैसे गन्ना भगवान ने बनाया, लेकिन उसको पेरना और उससे शक्कर बनाना मनुष्य का काम है। भगवान ने हम को पृथ्वी और आकाश दिये, मनुष्य के काम की जितनी चीजें हैं, वे पैदा कीं, व चीजें सब को बराबर मिलें, लेकिन मिलती नहीं हैं, सब कुछ अधिकारियों पर निर्भर है। गांव के

सभापति से लेकर राष्ट्रपति तक के कोई अधिकार नहीं हैं, सब अधिकार विध्यासघाती नौकरो के हाथ में हैं। आज किसी दारोगा को रुपया दे दो, तब तो कुजल है, वरना कहंगा कि बलो, अदालत में। अदालत में जाकर देखिये—ये काला काला जामा पहने नैकडो बकील भूमते रहते हैं, जो किसानों को खा जाते हैं। जवाहर लाल नेहरू के जमाने में चलते हुए मुकदमे आज भी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, बकील मर गये, लेकिन फाइलें वही पडी हुई हैं। यह क्या विधान है, जो फौमला जल्दी होना चाहिए, वह नहीं होता है। आज अमरीका और दूसरे मुल्को के लोग अपने एजन्टों के द्वारा हमारे यहां अष्टाचार का प्रचार कर रहे हैं, ताकि यहां अशान्ति फैले, अराजकता फैले, और हमारी सरकार फेल हो जाय हमका नतीजा बहुत खराब निकलेगा। हमें इस तरफ बहुत गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए।

अन्त में, मैं अपने मंत्रियों और सब को बता देना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ नौकरो के हाथ में है।

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का जो भाषण है उसका मैं समर्थन करते हुए कुछ बातें उस सिलसिले में कहना चाहता हूँ। माननीय शरद् यादव जी, जो जबलपुर क्षेत्र से चुन कर आये हैं उन्होंने परसों बबरबन के समय कहा था कि वह हिन्दी प्रान्त से आते हैं। तो कम से कम उनको यह समझना चाहिए कि हिन्दी का कोई प्रान्त नहीं होता बल्कि हिन्दी का देश होता है। भारतवर्ष की भाषा हिन्दी है। अगर वह प्रान्तीय भाषा हैं उनके अनुसार, तो मैं आन्ध्र प्रदेश से आ रहा हूँ और तेलगू बोलने वाला हूँ मैं किसी और प्रान्त की भाषा को क्यों सीखूँ? तो हिन्दी जिनकी मातृभाषा है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दी किसी प्रान्त की भाषा नहीं बल्कि देश की भाषा है।

मुस्लिम लीग के सदस्य माननीय कोया ने भाषण देते हुए जो कहा कि कम्युनल फीलिंग, खास कर केरल में अभी भी मौजूद है, उस बाते में मेरा कहना है कि जो जान्डिम का मरीज होता है उसको पूरी दुनिया पीली ही नजर आती है। क्योंकि ऐसे ही लोगों ने देश का बटवारा किया है और वही मुस्लिम लीग का नाम रख कर फिर सामने आ रहे हैं। अब और क्या वह देश का करना चाहते हैं? आज कोई हिन्दू और मुसलमान नहीं है बल्कि सब भारत के नागरिक हैं। परसों जामा मस्जिद एरिया में मैंने देखा कि मुसलमानों का साथ हिन्दुओं ने दिया। गरीब मुसलमान केरल में कोई है ही नहीं। आन्ध्र में जरूर गरीब मुसलमान हैं क्योंकि निजाम के जमाने में जिन्दगी का दारोमदार नौकरो पर था, और धीरे धीरे अब सब रिटायर हो गये हैं। तो जो मुस्लिम स्टेट्स थी वहां जरूर यह प्रोबलम है, उसको हल करने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत तेजों से काम कर रही है। इसलिये साम्प्रदायिक बाते यहां नहीं करनी चाहिये

Some time the defaulters are also uttering scriptures

वह खुद कम्युनल है और दूसरों को कम्युनल बनाने की कोशिश करते हैं।

माननीय वाजपेयी जी सदन में और सदन के बाहर कहते रहे हैं कि हम को 1971 की गरीबी वापस दे दे, और यह कह कर वह समझते हैं कि उनकी बात ठीक है। अगर 1971 की गरीबी वापस दे तो बांगला देश को पाकिस्तान को है छोबर करने का आप का मतलब है क्या? बांगला देश की लडाई हम ने लडी है और जहां पहले 200 करोड रु० का मिलिटरी का बजट होना था आज वह बढ़ कर 2,000 करोड रु० का कर रहे हैं हमारे रिस्त्र मंत्री जी। तो बांगला देश को आजाद कराने के वास्ते कितनी मेहनत और पैसा हम को खर्च करना पडा। अगर सेन्टीप्रदास किये हुए कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।

[श्री एम० राम० गोंपाल रेड्डू]

बांगला देश को आजाद कराने में हमने मदद दी, आज वह एक सेक्यूलर स्टेट है। हर रोज जो वहाँ से शरणार्थी आते थे जो हमारे ऊपर एक बोझ था वह कम हो गया है। उसकी कीमत आज हम को भुगतनी पड़ रही है। एक हजार साल में हम को इतनी शानदार फतेह नहीं हुईं जैसी 1971 में हुई है। तो उनके लिये कुछ खर्च करना पड़ता है और तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिये यह कहना कि उस वक्त आप खुश थे और आज नहीं है, वह फतेह पाने के बाद देश आज खुश नहीं है, यह ठीक नहीं है और न विरोधी दलों को ऐसा कहना शोभा देता है।

अणु शक्ति का शानि के लिये प्रयोग करने में खर्चा हो रहा है। और बाम्बे हाई मे जो सागर सम्राट है, जिसके जरिये तेल की खोज की जा रही है, उसके वास्ते भी पैसा लगाना पड़ता है। तो एक दम तो हम इन प्रयासों का फल नहीं पा सकते। यह पैसा तो आने वाली पीढ़ी के लिये खर्च किया जा रहा है। आज का लाभ हम नहीं देख रहे हैं। जैसा रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था "शत वर्ष परे" उसको ध्यान में रख कर काम किया जा रहा है। प्लानिंग पर 25 साल का अन्दाजा लगा कर खर्च कर रहे हैं।

मेरी शिकायत है परसो रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की तनक्वाह और डी० ए० बढ़ाने की क्या जरूरत थी जब कि आप ने एक० आई० सी०, एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस को कुछ नहीं दिया। रिजर्व बैंक में जो नौकर है उनका जितनी तनक्वाह मिल रही है और काम कम है, फिर उनको ज्यादा तनक्वाह देने की क्या जरूरत है, यह मैं जानना चाहता हूँ? अगर वह स्ट्राइक करते हैं तो करने दीजिये। अपने देश में काफी पढ़े लिखे नौजवान हैं। अगर रिजर्व बैंक के लोग जाना चाहते हैं तो उन सब को निकाल कर नये लोगों को आधी तनक्वाह पर भर्ती कीजिये।

एक तरफ आप कहते हैं कि इनफ्लेशन हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार खुद तनक्वाह बढ़ाती है। यह ठीक नहीं है।

बैल्ड टैक्स और इन्कम टैक्स से जिसके पास भी ज्यादा आमवनी और धन हो उसको जब्त कर लिया जाय। हमने यह कानून पास किया था कि जो 100 रुपये के माल की 50 रुपये में रजिस्ट्री कराता है तो सरकार को उस बीज को ऐम्बायर करना चाहिये। लेकिन उसका एम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। इससे ब्लैक मनी रोका जा सकता है।

अब मैं आन्ध्र प्रदेश की तरफ आता हूँ। हमने गुजस्ता साल 4 लाख टन अनाज, चावल दिया और इस साल 7 लाख टन दे रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने केन्द्र को लिखा है आइन्दा आज से 10 लाख टन देने वाले हैं सिर्फ नागार्जुन सागर में पूरा पानी भरा हुआ है उसको खेतों तक पहुँचाने के लिये कैनल की आवश्यकता है। कैनल नहीं बनी है। यह कौन सा प्लानिंग है। कैनल बनाने के वास्ते हमको 100 करोड़ रुपये चाहिये, यानी 20 करोड़ रुपया प्रति साल के हिसाब से और उनके बदले में हम 3 लाख टन चावल ज्यादा देने वाले हैं। बाहर से अनाज मंगाने से अच्छा यह है कि आप नागार्जुन सागर, सिबसेलम और पाच-पांडव प्रोजेक्ट्स को पूरा कर दें। यह योजनाये 15,20 साल से पडी हुई हैं और उनकी कीमत भी बढ़ रही है। रिजरवायर बनाया गया है, पानी का स्तर आ गया है और उसको निकाल कर कैनल तक ले जाने का कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा कर,या जाय। बहुत से केरल के एम० पी० नागार्जुन सागर आये थे, उन्होंने कहा अपनी सरकार से बोलें कि थोड़ी रकम आन्ध्र प्रदेश के इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने के वास्ते दी जाय।

मैं यह कहना चाहता हू कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनकी आन्ध्र प्रदेश के वास्ते कोई जरूरत नहीं हैं। हम तो देश को घनाज सप्लाई करना चाहते हैं। कई दफा यह कहा गया है कि इन प्रोजेक्ट्स को सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट में स्टेट का दो दो ती करोड़ रुपया खर्च हुआ है और दूसरे स्टेट्स में जो हैं वे अपना पैसा ले जा कर इन्स्टीट्यूट में लगा रही हैं जिनसे वहां पर इण्डस्ट्रियल पोटेण्शियल क्रिएट हो गया है और लोगों को नौकरी मिली है और हम पूरे के पूरे जमीन के ऊपर अपना भरोसा लगायें हुये बैठे हैं। इसलिय मैं पुरजोर अपील करना चाहता हू कि कम से कम तीन मालो में तो पूरी प्रोजेक्ट्स कमलीट हो जाने चाहिये।

एक आखरी बात मैं और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि जिस तरीके में देश को आगे बढ़ना चाहिये, उस तरीके से आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि हर साल एक करोड़ 30 लाख आदमियों का इजाफा होता जा रहा है।

All this is increasing with compound interest

इसकी जिम्मेदारी हमारे जनसभ और मुस्लिम लीग पर है। ये दो पार्टिया अपने देश में ऐसी हैं जो कि फैमिली प्लानिंग के खिलाफ जहर उगलती रहती है। तो मैं पूछना चाहता हू कि एक तरफ इतनी आबादी आप बढ़ाने जायेंगे और दूसरी तरफ इन्दिरा जी से बोलेंगे कि हमें खाना खिलाया, हमें कपडा दो और हमें नौकरी दो, तो कैसे दोनों बने हो सकती हैं। जिन बक्त देश आजाद हुआ था, उस बक्त काबले-कास्त जमीन अगर सब लोगों में बाटी जाती, तो एक आदमी को लगभग एक एकड़ के आता था नैन आज जो है *Three-fourth of an acre we are getting if it is divided uniformly.*

तो तीन चौथाई में एक आदमी को पालना पड़ता है जब कि अमेरिका में पर है 6 एकड़

हैं और जहां अमेरिका के प्रेसीडेंट को एक आदमी को खिलाना पड़ता है वहां हमारी प्रधान मंत्री को 6 आदमियों को खिलाना पड़ता है। उनको वहां एक आदमी का इन्तजाम करना पड़ता है जब कि यहां पर 6 आदमियों का इन्तजाम करना पड़ता है। इसी तरह से रूस में 5 एकड़ पर है 6 आदमी है। इसलिये मेरा कहना यह है कि मेहरबानी करके फैमिली प्लानिंग सबके ऊपर लागू करें और उस पर सब्जी से भ्रमल होना चाहिये नहीं तो देश में प्रगति नहीं हो सकती है। इस वास्ते मैं चाहता हू कि थोड़ी सी विल पावर हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिये, पार्लिटीकल पावर हूनी चाहिये और पार्लिटीकल टिमिडिटी को छोड़ना चाहिये। यह कानून बना देना चाहिये कि किसी महा-शय के दो में ज्यादा बच्चे नहीं होंगे और अगर तीसरा बच्चा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर है स्टेट पर नहीं। वह अपनी मर्जी से जहां चाहे पढाये और अपनी मर्जी से नौकरी कराये। हमारे चाइना के भाई बहुत सी बातें कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके कितने बच्चे हैं ?

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी : मेरे दो हैं, एक बच्चा और दूसरी बच्ची।

अध्यक्ष महोदय : तभी आप यह कह रहे हैं।

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी : मैं आयन्दा के वास्ते कह रहा हू। मैं यह नहीं कहता कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो।

मैं यह कह रहा था कि ये चाइना के भाई जो यहां फैले हुये हैं, यह पार्लियामेंट का सेशन अगर कम चले तो ची-गुकार करते हैं और चाइना में दस माल के बाद एक दफा सेशन हुआ, तो कुछ नहीं कहते हैं।

बस मुझे इतना ही कहना था। बैंक पू. सर।

अध्यक्ष महोदय : मि० यादव, आपको कल बोलने के लिये बुलाया था, तो क्या आप बोलने के लिये खड़े हुये थे ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : (मधेपुरा) : कल मैं खड़ा हुआ था। इसके बाद हाउस एजोर्न हो गया। इस के बाद मंत्री महोदय ने बताया कि आपका बाद में नम्बर आएगा और मैं इसी इम्पेशन में रहा। मैं माफी चाहूंगा और आप से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे फिर से समय दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : उसी वक्त हाउस एजोर्न हो गया था, तो फिर मैं आपको इनके बाद टाइम दे दूंगा।

श्री शिव कुमार शाल्मी (भरौली) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी को इस बात के लिये उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में पढ़ा, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो धारणा प्रथम राष्ट्रपति ने प्रारम्भ की थी और बीच में अवरुद्ध हो गई थी, उसको फिर उन्होंने प्रवाहित किया, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

जहाँ तक भाषण का सम्बन्ध है, वह कोई उत्साहवर्धक नहीं है। देश के सामने जो विकराल समस्याएं थी, उनको गंभीरता से विश्लेषण करके जो समाधान उपस्थित करना चाहिए था वह भाषण में नहीं है। महंगाई, भुखमरी, छात्रों और युवकों में बढ़ती हुई अपराध की वृत्ति, वे इस प्रकार की समस्याएं हैं, जिनका कुछ विश्लेषण करके समाधान उपस्थित करना चाहिए था। इस समय जो क्षणिक बात है जिसमें तथ्य उतना नहीं है लेकिन प्रचार अधिक किया जा रहा है कि महंगाई कम हो रही है, वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हैं, कल बाजार में जाकर विशेष रूप से मैंने कुछ छानबीन की तो सरसों के तेल को छोड़कर कहीं 10 पैसे की कमी हुई है और किसी में 20 पैसे की कमी हुई है। जो इतनी अधिक महंगाई बढ़ गई थी, वहाँ केवल इतने

से ही सत्पुष्ट हो जाना कि अब कीमती गिरने लगी हैं, यह आत्म प्रबंधना है, यह अपने को धोका देने के बराबर है। राष्ट्रपति ने इन समस्याओं का सरसरी तौर पर जिक्र किया है और फिर यह संतोष व्यक्त किया है कि देश के सामने अब आने वाला जो समय है, वह अच्छा होगा और सुखद होगा और फसल अच्छी होगी और इस तरह से जो कठिनाइयाँ हैं वे दूर हो जायेंगे। इस तरह का आश्वासन देते देते लगभग 27 वर्ष गुजर गये हैं और मुझे इस बात पर एक शायर का शेर याद आता है :

यह कह कह कर के शव भर
तरसाया मेरे साझी ने,
यह खुम प्राया, यह शीशा प्राया
यह पैमाना आता है ॥”

इस तरह से यह कहने कहने कि अब यह हो रहा है, अब वह हो रहा है और सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, 27 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। मेरे पूर्व के लगभग प्रत्येक वक्ता वे, जो इस समय बहुत बड़ा आन्दोलन हमारे देश में चल रहा है उसका जिक्र किया और ऐसा लगता है कि प्रत्येक के मस्तिष्क पर श्री जय प्रकाश नारायण छाये हुए हैं। जो भी वक्ता उठता है वह उस बात का प्रायः जिक्र करता है। सोचना यह है कि जो बातें श्री जय प्रकाश नारायण ने कही हैं, उनमें जो ऐसी बातें हैं जिनको हम सब स्वीकार करते हैं, उस आन्दोलन के प्रकाश में उन कमजोरियों को और उन त्रुटियों को दूर कर लेना चाहिए। कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दो तीन बार इस बात पर बहुत जोर दिया कि श्री जय प्रकाश नारायण ने पुलिस को और फौज को जो बातें कही हैं, बिरोधी दल के लोग उस बात से कहा तक सहमत हैं, वे इस बात को स्पष्ट करें। तो क्या इन्द्रजीत गुप्त जी और उनके दूसरे साथी यह समझते हैं कि जो बातें बिरोधी दल वाले ठीक नहीं समझते, उनमें भी वे श्री जय प्रकाश नारायण के साथ बंधे हुए हैं ? उदाहरण के लिए मैं एक बात को लेता हूँ।

यह बात स्पष्ट है कि काश्मीर में शेख अब्दुल्ला को जिस समय सत्ता सौंपी गई, तो जन सच ने उसका विरोध किया है, बी०एल०डी० के नेता चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया है हालांकि श्री जय प्रकाश जी ने उसका स्वागत किया है जब शेख अब्दुल्ला उनसे मिलने के लिए गांधी प्रतिष्ठान गये थे। इससे यह बात स्पष्ट है कि विरोधी दल जिस बात को ठीक नहीं समझते, उस बात के लिए वे जय प्रकाश नारायण जी के साथ बंधे हुए नहीं हैं बल्कि अपनी राय जैसी वे रखने हैं, वे प्रकट करते हैं, लेकिन एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने के योग्य है, वह यह है कि श्री जय प्रकाश नारायण का भ्रान्दोलन चार बातों के आधार पर है और उनमें सुधार हमें करना चाहिए। केवल अपनी जिद्द पर भरे रहना और अपनी दृष्टि को दृष्टि न मानना, यह उचित नहीं है और राष्ट्र के हित में भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपका टाइम तो खत्म हो चुका था। केवल दो मिनट थे। आप बार-बार कह रहे थे, इसलिए मैंने आपको समय दे दिया। आप एक मिनट में खत्म कीजिये।

श्री शिव कुमार शाल्मी : कुछ समय और नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : फिर औरों के समय में से देना होगा। चार, पांच मिनट तो दे दिये हैं। आप एक दो मिनट में खत्म कीजिये।

श्री शिव कुमार शाल्मी : मैं निवेदन कर रहा हू कि श्री जय प्रकाश नारायण के भ्रान्दोलन के चार स्तम्भ हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है पहला है बेरोजगारी। इसको दूर करने के लिए आप कौन से विशेष प्रयत्न देश में कर रहे हैं। देश में बड़ी भारी मशीनें काम करती हैं। एक भादमी एक मशीन को चलाता है और सौ भादमियों को बेरोजगार करता है। इस वास्ते छोटे-छोटे उद्योग चलने

चाहिए और जो भारी उद्योग हैं और भारी कारखाने हैं, जिनको आपने प्रारम्भ किया है उनमें जो माल पैदा होता है उसकी देश में खपत कम से कम हो और उस माल को दूसरे देशों में भेजा जाना चाहिए। इससे बेरोजगारी कम होगी। साथ ही देश में छोटे छोटे उद्योग प्रारम्भ किये जाने चाहिये ताकि अधिक से अधिक भादमी उनमें सच सके। इस प्रकार की कोई बात सरकार के सामने हो, यह हमें दिखाई नहीं देता है।

दूसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार के निराकरण की कही है। आप देख लें कि आपने जो रोजगार दिलाने के लिए दफ्तर खोले हैं उनमें भी लोगों को भ्रमना नम्बर निकलवाने के लिए भेट चढ़ानी पड़ती है और रिश्वत देनी पड़ती है, तब जा कर नम्बर निकल पाता है। जिधर आप देखें उधर भ्रष्टाचार है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए था लेकिन वह नहीं है।

13 hrs.

तीसरी बात महगाई की है। उत्पादन बढ़ेगा तब यह कम होगी। कभी ऋतु की कृपा से फल अच्छी हो जाती है तो उसका तो श्रेय आप ले लेते हैं और अगर कभी खराब हो जाती है तो प्रकृति के मत्ते आप सकट का दोष मढ़ देते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपको कुछ विशेष प्रयत्न करने चाहिए थे। जहा तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है बिजली के लिए आप कहते हैं कि कारखानों के लिए उतनी नहीं दी जाती है जितनी किसानों को दी जाती है किसानों को ज्यादा मिलती है। लेकिन देहातो में जा कर आप देखें। पंद्रह मिनट के लिए मा जाती हैं और फिर एक घंटे के लिए गायब हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो मजदूर खेती के काम के लिए रखे भी जाते हैं वे भी बेकार हो जाते हैं। किसानों की ओर जितना ध्यान होना चाहिए नहीं है जितना उनको खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए नहीं दिया गया है।

[श्री शिव कुमार शास्त्री]

चौथी बात है शिक्षा की। आप देख लें कि जहाँ जहाँ पर कालेज हैं, बी० ए० और एम० ए० में लड़के पढ़ते हैं वे चोरियों और शाकों में पकड़े गये हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप देखें कि कल को ही ये भारत के भाग्य विधाता बनेंगे तब इस शिक्षा क्या बनेगा? शिक्षा को आप क्यों नहीं बदलते हैं। धार्मिक शिक्षा देने का आप प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं। अगर वह नहीं देते हैं तो मारल शिक्षा, नैतिक शिक्षा यह तो प्रारम्भ होनी ही चाहिए।

इसके साथ साथ जो नई शिक्षा की पद्धति यहाँ दिल्ली में तैयार हुई है उसमें संस्कृत को निकाल दिया गया है। संस्कृत एक भाषा ही नहीं है बल्कि वह हमारी संस्कृति की धाती है। आपका पुराना भारत उसमें है। यह बहुत बड़ा अपराध है कि संस्कृत को उसके उस स्थान से बंचित कर दिया गया है जो बहुत प्राचीनकाल से उसको प्राप्त था। मैं कहूँगा कि संस्कृत का वही स्थान रहना चाहिए जो आज तक उसे प्राप्त था।

समयाभाव के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

MR. SPEAKER: Mr. Yadav, I just believe in what you have said that you had just got up when the House had adjourned. So, I am giving you an opportunity, but you should be here at 5 minutes to 2 p.m.

13.05 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

RE-DEMONSTRATION BY DELHI TEACHERS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. R. P. Yadav.

श्री रामबतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली के हजारों-हजार शिक्षक, औरत-मर्द, बोट क्लब पर अपनी मांगों के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं और सुना है कि प्रधान मंत्री जी और कई लोग सरकार की तरफ से पहले आश्वासन दे चुके हैं फिर भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं।

अभी वहाँ माननीय सदस्य श्री भगत भी गये थे, कुछ और पार्लियामेंट के मेम्बर भी गये थे। मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह यहाँ कोई बयान दें कि उनके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, नहीं तो एक बहुत भयंकर आन्दोलन की तैयारी वे कर रहे हैं जिसको संभालना सरकार के लिये मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं चाहूँगा कि सरकार एक बयान दे और उनके साथ समझौता वार्ता करके शीघ्र मसले को हल करे, वरना वे सब शीघ्र श्री जय प्रकाश नारायण की गोद में चले जायेंगे। इसलिये उनको बचाने के लिये यह जरूरी है कि उनके साथ समझौता किया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhagat, why do you want to join in this?

श्री एच०के० एम० भगत : (पूर्व दिल्ली) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि दिल्ली टीचर्स का मामला बहुत घसें से पेड़िंग है। उसका सील्सुमन निकालना चाहिए। उनके साथ बातचीत करके इसका जरूर समाधान निकालना चाहिए।